LOK SABHA

Thursday, July 6, 1967/Asadha 15, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker: Dr. Lohia, 961.

Shri S. S. Kothari: Sir, 961 may also be taken up with this question

Mr. Speaker: That is a different question.

आयकर का अपवंचन

+

*961. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने प्रोफेसर निकोलस कालडर द्वारा किये गये इस मूल्याकन पर विचार किया है कि भारत में प्राय: 200 से 300 करोड़ रुपए तक की आयकर की राशि का अपवंचन किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो आयकर को, जिसका अब भी अपवंचन किया जा रहा है वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये है और उनके क्या परिणाम निकले है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) : जी हां।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 929/67]

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल के भाग (क) के बारे में पूछना चाहता हू कि क्या प्रोफेसर कालडर ने जो रपट दी है उस से सरकार भी एक मत है या सरकार का मत है कि उस से भी अधिक आयकर की राशि का अपवंचन किया जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकारी नौकरशाहों, मंत्रियों और ससद सदस्यों इत्यादि की सुविधाओं को जैसे समझिये मकान का किराया है, आज बाजार भाव के अनुसार तो वह 10,000 रुपये का हो लेकिन वास्तव में देना पड़ता है खाली 600 या 700 रुपया महीना और जो पूजीपति लोग है उन का खर्चा खाता, एक्सपेंस एकाऊंट जिस को कहते हैं वह भी जोड़ दिया जाय तो फिर कितनी राशि आयकर के रूप मे बचेगी ? अगर सरकार ने यह हिसाब अभी तक नही लगाया है तो क्यों नही लगाया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहा तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है यह कहना बडा मुश्किल है कि आयकर का अपवंचन कितना हुआ है। यह अनुमान उन का है और वे अनुमान दे सकत ह। जहा तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है उस के बारे में मुझे इस वक्त कोई सूचना नही है कि कितनी बचत होगी।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस पहले सवाल को लेकर मंत्री महोदय थोडा सा और कष्ट करे। एक अनुमान उन्होने बतलाया है कालडर साहब का तो अपना अनुमान उन की सरकार का खुद का जो अनुमान हो वह भी बतलाते चले।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, कोई निश्चित अनुमान तो मेरे पास है नहीं मगर यह हम कोशिश करते हैं कि जहां कहीं पता चले उस को रोका जाय लेकिन कितना करोड है यह बतलाना बडा मुश्किल है। अगर यह मालूम हो जाय तो हम उस को रोकने की कोशिश करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे बार-बार आप से शिकायत करनी पडती है कि बेकार ही सवाल रहते है, खैर अब मैं दूसरा अपना बेकार सवाल पूछे लेता हू।

क्या मंत्री महोदय को पता है कि एक सज्जन जो प्राचीन भारत की अंतिम राजधानी के चेयरमैन रहे है और जो वहा की जिला कांग्रेस के एक सहारा भी हैं पिछले 12 वर्ष से अपना आयकर नहीं दे रहे है तो क्या कारण है कि उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

एक माननीय सदस्य : उन का नाम बतलाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : सेठ मैं ने बतला दिया कि प्राचीन भारत की अंतिम राजधानी यानी कन्नौज। यह सवाल पहले यहा पूछा जा चुका है इसलिए नोटिस की बात आप मत उठाइये।

श्री स० मो० बनर्जी : नाम बतला दीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया बतला तो दिया कि सेठ है उन का नाम ही सेठ है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त अब हर एक चीज के बारे से मुझे नहीं मालूम है इसलिए नोटिस तो मागना ही पडेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब यह सवाल यहा पहले आ चुका है और तब भी यही उत्तर दिया गया था। इसलिए अब मैं अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करता हू कि बिना मेरे कुछ कार्यवाही किये यानी अब मुझे कोई उस के लिए खत वगैरह न लिखना पडे क्योंकि मेरे जैसे लोग भी थक जाते है, आप इन दोनो सवालो का उत्तर शीघ्र से शीघ्र दिलवा दीजियेगा। एक तो यह कि क्यो नहीं उन सज्जन के खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है और दूसरे जो मैं ने पहले अनुमान वाली बात बताई कि अगर खर्चा खाता पूजीपतियो का और नौकरशाहों इत्यादि की सुविधाओ वाला हिसाब भी जोड दिया जाय तो कितना ज्यादा रुपया बच पायेगा ? इन दोनो सवालो का मेरे बिना कहे हुए आप अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवा दीजियेगा।

Mr. Speaker: I do not know, can it be given to the House

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : डा० साहब जो मागते हैं वह देने के लिए हमारी कुछ तैयारी नहीं ऐसा तो नहीं है मगर उस का अदाजा लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि पूजीपतियो का जो खर्चा जाता है उस मे से कुछ खर्चा तो देना ही पडता है क्योंकि आखिर वह काम के लिए है और वह खर्चा न दे तो काम चलेगा नहीं। इसलिए उस मे से कितना बचा या नहीं बचा और कितना खर्चा हेम बचावे और कितना आयकर बच जायेगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है। परन्तु इतनी इतनी बडी उम की सख्या नहीं हो सकती ऐसा मैं मानता हू। हा, 10–15 करोड रुपया हो सकता है उस से ज्यादा तो नहीं हो सकता है।

श्री रवी राय : यह क्या कम है ?

श्री मोरारजी देसाई : वैसे तो एक रुपया भी कम नहीं है। मैं उसको कम नहीं मानता मगर वह भी कहना मुश्किल है

डा० राम मनोहर लोहिया : अरबों का मामला है।

श्री मोरारजी देसाई : अरबों का मामला तो इसमें आ ही नहीं सकता।

डा० राम मनोहर लोहिया : अरबो का सुविधाओ का मामला ।

श्री मोरारजी देसाई : कुछ सुविधाए तो देनी ही होती हैं उनको कैसे ले ले ?

डा० राम मनोहर लोहिया . हा, अरबो का मामला है ।

श्री मोरारजी देसाई मैं कुछ ऐसा सोच रहा हू कि इस सुविधा को देने की जरूरत ही न पडे और उसके पहले ही हम कुछ इन्तजाम कर ले अगर किसी भी तरीके से कर सकते हैं । वह सोचना होगा । जितना कहना आसान है उतना करना आसान नही हैं । मैं मानता हू कि 4–6 महीने मे इस बारे मे कुछ नतीजा निकलेगा ।

दूसरा मामला जो डाक्टर साहब ने बतलाया अब उनका नाम न ले तो मुझे कैसे पता चले कि और मैं किस की इनक्वायरी कराऊ ?

डा० राम मनोहर लोहिया : उन का नाम सेठ है । कन्नौज नगर पालिका के चेयर मैन हैं । चेअरमैन एक ही होता है ।

श्री मोरारजी देसाई : कब चेअरमैन थे ?

डा० राम मनोहर लोहिया · अभी चेअरमैन है और पिछले 12 साल से हैं । क्या बात आप कर रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई मैं ठीक बात कर रहा हू । मैं इस तरीके से जाच कराने के लिए तैयार नहीं हू । इसका जकर नोटिस देना पडेगा ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह जो निकलोस काल्डर की रपट है वह मेरा ख्याल है 10 साल पहले की है । उसके बाद पूंजीशाह, बडे नौकरशाह और मन्त्रीशाह के भ्रष्टाचार जो सिलसिले हैं वह बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है । मेरा ख्याल है कि अब करों की चोरी के आकडे 500 करोड के लेकर 700 करोड के बीच में होंगे । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या इनकम टैक्स के मुहकमे मे जो भ्रष्टाचार है और मन्त्रियो द्वारा जो उन को बचाया जाता है तो उसकी जाच करायेंगे (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य यह बात गलत है ।

श्री मधु लिमये : कई उदाहरण दे चुका हू । धीरज रखिये अभी तीसरा ही सवाल आने वाला है । अध्यक्ष महोदय, यह लोग जानते बूझते तो कुछ हैं नही व्यर्थ मे ही इस तरह होहल्ला मचाने लग जाते हैं । अभी मेरा तीसरा प्रश्न सदन के सामने आने वाला है । साढे 56 लाख की चोरी का मामला मैंने पकडा है । बेकार मे यह इस तरह से हल्ला मचाते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप इन को शात करिये ।

Mr. Speaker· This is the Question Hour Let us know the question first

श्री मधु लिमये : मैं यही पूछ रहा था कि क्या मन्त्री महोदय इस इनकम टैक्स विभाग के काम के बारे मे जाच करेंगे जिससे कि जो यह 500 से लेकर 700 करोड रुपये के इनकम टैक्स की चोरी हो रही है और अगर यह चोरी बन्द कर दी जाए समाप्त कर दी जाय और बकाया इनकम टैक्स वसूल कर लिया जाय तो सरकार को आवश्यक चीजो पर कर लगाने की जरूरत नही पडेगी, क्या मत्री महोदय इसके बारे मे व्यापक जाच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री मोरारजी देसाई: इसमे आकाश तक की व्यापक जांच करने की कोई गुजाइश नही है । माननीय सदस्य कहते हैं कि 500 से 700 करोड तक आयकर गुम हो जाता है । कोई भी कुछ अन्दाजा लगा सकता है, एक हजार भी कह सकता है, दो हजार भी कह सकता है, दो सौ भी कह सकता है । लेकिन कुछ होता है इसमे शक नही है । यह मैं भी कबूल करता हूं । जो होता है उसके पीछे हम पडे हुए हैं और मैं मानता हू कि उसमे कुछ सफलता मिलेगी । लेकिन ऐसी सफलता कभी होने वाली नही है कि सारे का सारा मिल जाये और कुछ बाकी न रहे ।

श्री रवी राय : मैं जानना चाहता हूं कि कि कलिंगा ट्रस्ट के सिलसिले में वित्त मन्त्रालय की ओर से और इनकम टैक्स विभाग की ओर से जो जांच बीजू पटनायक की हो रही थी, उसका क्या नतीजा निकला । मैं जानता हूकि उडीसा के दो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरे कृष्ण मेहताब और श्री नवकृष्ण चौधरी गवाही दे चुके है । कलिंगा ट्रस्ट के सिलसिले में इस वक्त वित्त मन्त्रालय क्या कर रहा है और उनके ऊपर कितना इनकम टैकुस बाकी है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह जो सवाल हैं उसमें व्यक्तिगत सवाल का जवाब देना मेरे लिये कठिन है ।

श्री रवी राय : इसमें व्यक्तिगत बात क्या है ?

Mr. Speaker: He is referring to individual cases.

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो विवरण सदन के सामने रखा है प्रश्न के जवाब मे उसमें यह बतलाया गया है कि जो सजा मिलती है उस को बढाया है । यह दुरुस्त बात नही है । इनके बाद दूसरे पृष्ठ पर कहा गया है कि 1964–65 की अवधि मे 28 मुकदमे चलाय गये और 7 और चलाने का प्रश्न हो रहा है । मैं जानना चाहता हू कि जब मन्त्रालय ने 1964–65 का नम्बर दिया तो क्या उनको 1965–66 का नम्बर मालूम नही है कि जिन लोगो के ऊपर मुकदमे चलाये गये उनमे से कितने लोगो को सजाये मिली ? मैं जानना चाहता हू कि क्या डिपार्टमेंट के लोगो के ऊपर भी मुकदमे चलाये गये ? और यदि चलाये गये तो कितनो को सजायें मिली ?

Shri K. C. Pant: I do not have the details with me now. But I would be prepared to furnish them if the hon. member wants.

श्री एस० एम० जोशी : जब यह लिखा हुआ है कि 1964–65 मे इतना हुआ तो क्या 1965–66 के बारे में मालूम नही है ?

Mr. Speaker: He says he has no information now He is prepared to furnish it

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : प्रो० कालडोर को भारत सरकार ने कर के सारे ढाचे का अध्ययन करने के लिये बुलाया था और उन्होने यहां इसका अध्ययन किया । उन्होने बतलाया यहा पर 200 से 300 करोड के बीच आयकर की चोरी होती है । क्या भारत सरकार ने इस बात की जाच की कि प्रो० कोल्डर कैसे इस निष्कर्ष पर पहुचे और क्या भारत सरकार ने उनके अध्ययन को ही अपने कार्यक्रम का आधार बनाया है ?

श्री मोरारजी देसाई : जब वह यहा पर आये थे तब उनसे बात हुई थी लेकिन वह कोई खास सुझाव नही दे सके जिसके आधार पर व्यापक कार्यक्रम बना कर हम काम करते ।

Shri S. S. Kothari: What is the Government's experience of the pilot scheme of functional distribution of work and what steps have been taken to apply it on an India-wide scale? Is it likely to improve efficiency and check evasion, in the Minister's opinion?

Shri Morarji Desai: Our experience of the pilot scheme is quite good and it is being applied on an All-India scale 50 per cent of of the work will be completed by next April and the next 50 per cent will be finished in 6 or 7 months after that

Shri R. Barua: Is the Government aware that under the cover of partnership law, income-tax is evaded by forming firms between sons, daughters and brothers? If so, does the Government propose to go into the entire matter and bring forward proper legislation?

Shri Morarji Desai: It is impossible to stop this unless you remove all partnerships altogether, which in my view is not possible or desirable. It cannot be done. Moreover, evasion is not being done only by these people in the name of their sons, daughters

or otherwise, evasion is being done by many people, specially by the smaller people also and all professional people also are involved in it—many of them are involved in it We are trying to find out how best we can see that evasion is not there

Shri S. M Banerjee: May I know whether it is a fact that one of the industrialists of Kanpur, Shri Ram Rattan Gupta evaded payment of arrears of income-tax to the tune of Rs 31 lakhs, ultimately it was found out by some income-tax authorities and later on the entire sum of Rs 31 lakhs was written off with the connivance of the income-tax authorities and, probably, a Minister who is now a Governor; if so, what action has been taken against those officers and whether re-investigation in this case has started under orders from the present Finance Minister?

श्री मोरारजी देसाई : यह व्यक्तिगत सवाल है ।

Shri S. M. Banerjee: Sir, I rise to a pomt of order This particular question started with evasion and not "written off"

Mr. Speaker: Whatever it is, you are asking about a particular case relating to Rs 31 lakhs It is an individual case and they will have to find out the details

श्री रवी राय : मन्त्री महोदय को कहना चाहिये कि उन्हें मालूम नही है ।

Shri S. M. Banerjee: Sir, I want your guidance in this caes If you kindly go through the statement you will find that there are various legislative measures and other measures which have been suggested. I wanted to know

Mr. Speaker: The main question is about general evasion of income-tax. If you ask about any individual case they will not be in a position to give the answer without looking into it If he gives an answer which is not correct then again there will be trouble.

Shri S. M. Banerjee Sir out of 200 or 300 cases, this case of Rs 31 lakhs also is one

Mr. Speaker: There may be thousands of cases, they cannot remember all the thousand cases

Shri S. M. Banerjee: This is a very glaring case about which everybody was informed.

Mr. Speaker: It is an an individual case.

Shri Hem Barua: Sir, it has been reported that Shri Biju Patnaik has evaded income-tax ..

Mr. Speaker: Again it is an individual case

Shri Hem Barua: I will connect it up with the general question. It has been reported that Shri Biju Patnaik has evaded income-tax to the tune of Rs 3 crores embracing all his enterprises and it was stated by the Minister of State for Finance, Shri Bhagat, on the floor of this House that he would make a statement about all these things before the elections took place No statement has been made up till now Now, to take shelter under the plea that this is an individual case does not satisfy us because it is a fact that income-tax is being evaded in this country. What is Shri Morarji Desai going to do to mop up all this evaded income-tax in this country?

श्री रवी राय : वह रक्षा कर रहे है बीजू पटनायक की ।

Mr. Speaker: The later portion is not individual—what is he going to do to mop up evasion in this country?

Shri Morarji Desai: As I said, we are going into this question deeply and trying to find out what methods we can find so that evasion is reduced to the minimum. In individual cases also I have no desire to keep back any information. I should not keep back any information. But it is not possible for me to give all the information here at this moment.

श्री मधु मिमये : पिछले वर्ष आश्वासन दिया था कि चुनाव के पहले यह आ जायेगा ।

Shri Hem Barua: Where is the statement?

Shri Morarji Desai: I will see whether it was promised or not. I do not myself know. I was not here then. Now that I am told it was promised I will look into it and if it has been promised I shall certainly put it before the House.

Shri Surendranath Dwivedy: It was an assurance given by the Government and not a personal assurance.

Shri Morarji Desai: If an assurance has been given I shall certainly put a statement before the House.

श्री मधु लिमये : पिछली बार भी मैंने कहा था । बीच में इतने दिन चले गये । अभी तक यह तैयार नहीं है । मैंने दस-बारह दिन पहले उठाया कलिंगा एयरवेज के सवाल पर था । मैंने दस बारह दिन पहले यह सवाल उठाया था ।

Shri Morarji Desai: If it is so, what prevents the hon. Member from asking a straight question about it, I do not know. I will not avoid it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया है । उस को स्वीकार नहीं किया गया है ।

Mr. Speaker: I too agree that this is an important question. There are no two opinions about it. If by some other method you call the attention of the Minister he will give all the details. Why depend on the promise of Shri Bhagat? If such a promise was made, well and good. But, even if it was not made, if the information is wanted, I am sure the Minister will furnish it.

श्री मधु मिमये : वह जानकारी नहीं दे रहे हैं । मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया, लेकिन उन्होंने उसको रिजैक्ट किया है । वह झूठ बोल रहे हैं ।

Mr. Speaker: When this point was brought to his notice he said that he is prepared to do it. He is not trying to evade it.

श्री मधु लिमये : इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कि शार्ट नोटिस क्वश्चन क्यों नहीं स्वीकार किया गया ।

Shri Morarji Desai: Sir, I want to raise an objection to what the hon. Member has said in his temper. He has said:

"वह झूठ बोल रहे हैं ।"

श्री मधु लिमये : "असत्य" कह लीजिए । एक ही बात है । असत्य बोल रहे थे ।

श्री मु० अ० खां : अध्यक्ष महोदय, इस लफ़्ज़ को प्रोसीडिंग्ज़ से एक्सपंज कर दिया जाये ।

Mr. Speaker: It is wrong. I have repeatedly held that the usage of the word 'jhoot' is wrong as it is unparliamentary. It should not be used. I have said it repeatedly on the floor of the House.

Shri Hem Barua: If a Member calls a Minister a 'liar' that can be objected to. But if he says that the Minister is telling a lie, it is a very innocent statement.

Mr. Speaker: I find that this matter is taking up the whole question hour. Now Patnaik has come into the picture and therefore they want to ask more questions. I am not concerned with that at the moment. Here the question is of a general nature. If individual cases are brought in, not one or two but ten or more or even hundreds of smaller cases, it will be difficult for the Minister to give a ready answer.

Shri Umanath: Patnaik has become a general question.

Shri Hem Barua: He has become an institution.

Mr. Speaker: I am not objecting to questions as such I only want that the questions should be asked and answers given in an orderly way, not put some question, bring in something else and then ask about Shri Patnaik on a general question. The question about Shri Patnaik may be important But does it mean that everybody should bear in mind that alone and nothing else counts in this world? That is very difficult Supposing in the answer the Minister gives some wrong information Tomorrow Members will catch hold of him, saying that some wrong information has been given Therefore in individual cases the Ministers have to be very careful in answering questions I am not saying that the House should not take up individual cases It can But there is a method for it, not on a general question

श्री मधु लिमये : यह मामला दस दफा यहां आ चुका है। शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उस को स्वीकार नही किया गया।

Mr. Speaker. If they do not accept a short notice question some other methods are there The rules provide many other ways We have a right to expect the Minister to give all the information But this is not the way to elicit information.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय नोटिस दिया है लेकिन आप इस ओर ध्यान ही नही दे रहे हैं। मेरे पास इन्कार का पत्र मजूद है। शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया है और उसको अस्वीकृत कर दिया गया है। आप कहते हैं कि नोटिस नही दिया है।

Mr. Speaker: Now does the House want to take another 20 minutes on this question?

Shri Morarji Desai: If the hon. Member wants to know why I did not agree to the short notice question, I say this is not of that immediate importance to be replied to on a short notice question Why does he not put an ordinary question?

श्री मधु लिमये : सवाल यह है कि उन्होंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन का रिजैक्ट क्यो किया। जहा तक महत्व का प्रश्न है क्या तीन करोड का मामला महत्वपूर्ण नही है? यह सरकार के आश्वासन का मामला है। उसको इसलिए स्वीकार नही किया गया है कि उसके ऊपर सप्लीमेंटरीज पूछे जायेंगे।

Shri Morarji Desai: I would say that if the hon Member had even written to me a letter asking for information I would have given fuller information I am prepared to give it any time he writes to me They can even publish it, if they like But if the hon Members get into the habit of losing tempers, I cannot help it

श्री मधु लिमये . यह मेरे और मन्त्री महोदय के बीच का मामला नही है बल्कि यह सदन और उनके बीच का मामला है।

श्री अब्दुल गनी डार : पायट आफ आर्डर सर। क्या किसी मिनिस्टर को चाहे वह डिपुटी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और हो यह अधिकार है कि वह अपने प्रेडेसेसर के दिये हुए किसी वादे के बारे मे कहे कि उसे उस वादे के मुताल्लिक कुछ पता नही है? मैं आईन्दा के लिए आप से यह रूलिंग चाहता हू कि जब एक पहले मिनिस्टर ने हाउस को यह यकीन दिलाया था कि स्टेटमेंट दिया जायेगा तो क्या किसी मिनिटर को यह हक हासिल है कि वह उसके मुताल्लिक लाइल्मी जाहिर करे। अगर फिनांस मिनिस्टर ने ऐसा कहा है तो क्या आप उनको इजहार अफसोस करने के लिए कहेंगे?

[پوائنٹ آف آرڈر سر - کیا کسی منسٹر کو - چاہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو - یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے پریڈیسیسر کے دئے ہوئے

کسی وعدے کے بارے میں کہے کہ اسے اس وعدے کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے - میں آئندہ کے لئے آپ سے یہ رولنگ چاہتا ہوں کہ جب ایک پہلے منسٹر نے ہاؤس کو یہ یقین دلایا تھا کہ سٹیٹمینٹ دیا جائیگا - تو کیا کسی منسٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے متعلق لاعلمی ظاہر کرے - اگر فلانس منسٹر نے ایسا کہا ہے - تو کیا آپ ان کو اظہار افسوس کرنے کے لئے کہینگے -]

Mr. Speaker: Suppose some Minister had stated something six months ago, if any Member thinks that the Ministers remember the whole proceedings of the House, I think it is too much of a presumption You can ask the Minister to verify and then give an answer But no Minister can be expected to remember what happened last year, which Minister gave which assurance in this House

श्री मधु लिमये : मैंने दस दिन पहले कहा था ।

श्री मु० अ० खां : अध्यक्ष म ो मेरा पायट आफ आर्डर है । आज हाउस में लफ्ज "झूठ" इस्तेमाल किया गया है । इसी तरह बराबर किसी को झूठा किसी को चोर और किसी को कुछ और कहा जाता है । मैं आप की व्यवस्था चाहता हू कि क्या इस तरह के अनपार्लियामेंटरी वर्डज हाउस में इस्तैमाल किये जा सकते हैं । मेरी दरख्वास्त है कि आज जो लफ्ज "झूठ" इस्तैमाल किया गया है उसको प्रोसीडिंग्ज से एक्सपज कर दिया जाये ।

Mr. Speaker: I have repeatedly said that this word should not be used. I have been trying to see that not only what they say but the serious objection which the Chair has taken must also go in print so that if anybody reads it in future he will read both the things, that the Member used this word and the Speaker said that it was not proper I want both the things to remain in the proceedings It is no use expunging it Every day somebody says that something should be expunged That is not the way I want it to stay in the proceedings so that the future generations and the next Parliament may read what kind of language we used

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह मामला अभी ठंडा हो जाता है अगर श्री मोरारजी देसाई अपनी उदारता में यह कह दें कि जितने मामले यहां पर उठाए गए हैं उनके बारे में वह एक व्यापक उत्तर जल्दी दे देंगे । अगर वह इतना कह देते तो सब मामला ठंडा हो जाता ।

Mr. Speaker: There is no point of order

श्री एस० एम० जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हू कि जब इस सदन में कोई इतना बड़ा सवाल उठाया जाता है तो उसके बारे में मालूमात दी जानी चाहिए । जब किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो उस का व्यक्तिगत प्रश्न कह कर टाला जाता है । जब यहां पर ये बातें बताई गई कि इनकम टैक्स चोरी करने वालों को हम इतनी इतनी सजा देंगे और इतने प्रोसीक्यूशन किये गए, तो क्या मंत्री महोदय के लिए यह उचित है कि वह कहें कि किसी प्रोसीक्यूशन का क्या हुआ, यह वह नहीं बता सकते हैं ?

Shri Tenneti Viswanatham: Some years ago there was investigation into tax evasion Now there is evasion on a large scale Is the Government prepared to appoint another investigation commission? Secondly, the Income-tax Investigation Commission's Re-

port disclosed various kinds of evasion practised Can the Minister tell us whether some of the important figures that figured in that report subsequently came into the list of Padma Bhushans?

Shri Morarji Desai I have no idea

Shri Hem Barua: On a point of order, Sir When a certain gentleman is awarded Padma Bhushan his name is recommended by the Government and when tax evaders become Padma Bhushans in this country, God save this country, I tell you Secondly, when the Minister pleads ignorance about that, that is also a very difficult thing for us to swallow Could you please instruct him not to say like that?

Shri M. Y. Saleem: Income-tax evasion is a common thing in all the countries of the world There are professional income-tax experts who openly advise the assessees how to evade income-tax Several books on this subject have been compiled by eminent authors In view of these facts is it practically possible to stop evasion of income-tax totally?

Shri R. K. Amin In view of the fact that Professor Kaldor must have calculated a sum of Rs 200 crores or Rs *300 crores on the basis of certain* loopholes in our tax structure, can you say on the same basis as to what is the estimate of evasion of income-tax today? Secondly, in view of the fact that it was the sale of import licences at a premium which was the main source of tax evasion, do you think that it is still the source of tax evasion and, if it is so, will you be prepared to get rid of import licences?

Shri Morarji Desai: The hon Member is a Professor and he should see that when Prof Kaldor says that the evasion is from Rs 200 crores to Rs. 300 crores, the difference is only of Rs 100 crores That is the estimate made and that estimate they want me to rely upon How am I going to do that When he says that import licences are the only mischief or one of them, import licences have got to be given when imports are to be obtained How are imports to be made then? Should we allow everybody to import whatever he likes? Who is then to pay and how is it to be paid for? All this the hon Professor does not seem to consider *(Interruption)*

श्री क० ना० तिवारी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । एक रोज पहले भी मैं ने यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था । एक सवाल के ऊपर आधा घंटा हो गया । आप ने कहा भी था उस रोज कि इसके ऊपर खास खास लीडर्स से बात कर के कोई तरीका निकालेंगे . .

Mr. Speaker: I entirely agree with you If my friends also cooperate, I would very much like to go to the next Question

श्री क० ना० तिवारी : इसमें कोआपरेशन का सवाल नहीं है । यह तो आप के डेसीजन का सवाल है ।

श्री शिव पूजन शास्त्री क्या मंत्री महोदय को पता है यह समाचार है 31 दिसम्बर 1966 का—कांग्रेसी उम्मीदवार गिरफ्तार । उस उम्मीदवार ने आय कर के 10 लाख रुपये चुराये थे । (व्यवधान) समाचार इस प्रकार है

> 'ज्ञात हुआ है कि श्री कामराज ने भारतीय कांग्रेस कार्यालय को लिखा है कि उस पार्टी उम्मीदवार की कथित गिरफ्तारी का पता लगावें जिन्हें आन्ध्र ससदीय क्षेत्र से टिकट दिया गया है । कहते हैं कि आय कर के दस लाख रुपये नहीं चुकाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है ।"

श्री शिवनारायण शास्त्री अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के जिम्मे चाहे वह साहू जैन हों, चाहे बिरला हों, चाहे वह टाटा हों, आप के पास रिपोर्ट है एस्टीमेट्स कमेटी की

भी और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की भी, जिन के जिम्मे बकाया है वह इनकम टैक्स आप उन से कब तक वसूल करेंगे ?

Some hon. Members *rose*—

Mr Speaker· I want guidance from the House now Do you want me to give another half-an-hour to this Question or go to the next Question? I do not want to call only one Member If I call one Member, I have to call others also It is not a question of calling only one Member If you want, you can have another half an hour on this Question

Shri Rajaram: Nobody has been called from my Party

Mr. Speaker. There is no party basis during the Question Hour

Shri Kanwar Lal Gupta: You may allow another five minutes on this

Mr. Speaker: You come to the Chair and let me see how you can finish in five minutes You want to put a question I know that Shri Umanath, this is the last supplementary (*Interruption*)

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । जनाब आप खड़े हैं तो साथ साथ वह भी खड़े हैं यह ठीक नहीं है ।

Mr. Speaker: I agree with you

Shri Bal Raj Madhok: Sir, you are in the Chair and it is for you to direct and control the proceedings of the House May we know from you whether it is not in your power to fix some time for each Question? We come prepared with questions One Question takes away all the time That is not proper It is not for the House to decide but it is for you to decide

Mr. Speaker: I wish the leaders of the parties also have some control over their party Members If they do so, they will be helping the Chair

Shri Bal Raj Madhok: We cooperate with you, you may fix some time for each Question

Shri Ranga: When some Member said that nobody had been called from his Party, you were kind enough to say that there is no party basis during the Question Hour Now, when it suits the Speaker, he turns round and asks the leaders of the parties to control their Members

Mr. Speaker. Shri Kanwar Lal Gupta has been getting up and his leader is sitting by his side He could have advised him not to get up when so much time has been spent on this one Question I agree with Shri Madhok that it is absolutely necessary to fix some time for each Question At least afer ten minutes, we should go to the next Question

Shri Surendranath Dwivedy· It is for you to fix the time It is at your discretion (*Interruption*)

Mr. Speaker I will do it now

Shri Umanath. I would like to know whether the Finance Ministry have sent instructions or propose to send instructions—I have put both the things, whether they have sent instructions or propose to send instructions—to their departments that income-tax returns upto Rs 10,000 may be straightway accepted without scrutiny, and if so, I would like to know from the hon Finance Minister how it is consistent with their stand that they are trying to reduce evasion and all that

Shri Morarji Desai: The instructions sent are with respect to returns upto Rs 7 500 and not upto Rs 10,000 This is not done in order to give complete freedom to anybody to do what he likes, but this is done in order to see that the assessments are made quickly But that does not mean that none will be examined after that What is proposed to be done is that 10 to 15 per cent of the cases out of these will be scrutinised and those who are found to have evaded will

be punished very severely That is the law I am trying to consider

Irrigation facilities during Fourth Five Year Plan

+

*962 **Shri Ram Kishan Gupta**
Shri Sidheshwar Prasad.

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state

(a) whether an outline of the irrigation facilities for the Fourth Five Year Plan has been finalised, and

(b) if so the broad details thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Not yet Sir

(b) Does not arise

Shri Ram Kishan Gupta May I know what will be the total allocation and the time by which it will be completed?

Dr. K L Rao I submit that the Fourth Plan has not yet been finalised in respect of irrigation Tentatively it is put up as Rs 825 crores and it will enable 13 million acres to be brought under irrigation

Shri Ram Kishan Gupta May I know whether the Beas Project will be completed during the Fourth Five-Year Plan?

Dr. K. L. Rao. The Beas Project I am afraid, will take upto 1972—one or two years later than the Fourth Plan

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां अक्सर सूखा पड जाता है और पानी की कमी रहती है, क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों को कोई विशेष सुविधा देने का प्रयत्न किया जायगा जिसमें वहां अकाल की स्थिति न आने पावे ?

Dr. K. L. Rao: It is true that some drought-affected areas, specially those which have been affected by the last two bad seasons, i.e., South Bihar and Eastern U P , must receive more attention that what they have received in the past I hope, this will be taken up and finalised in the Fourth Plan

Shri Mohamed Imam. So far as irrigation facilities are concerned, th State of Mysore has only about 7 per cent as compared to 24 per cent to 30 per cent in the neighbouring States This is not because there are no irrigation facilities, but there are a number of rivers which have not been harnessed May I know whether they will take into consideration the needs of the State of Mysore and resolve the disputes existing between Mysore and Madras, and Mysore and Andhra Pradesh, and till these disputes are resolved, will not take further steps or final conclusions?

Dr. K. L. Rao A very large number of projects have been sanctioned for Mysore It is true that the percentage of irrigation is rather low in the case of Mysore and Maharashtra It is expected that, with the completion of the projects that have been sanctioned, the percentage of irrigation will increase I must also say that the disputes between Mysore and the neighbouring States have not affected the progress of works

Shri Mohamed Imam: I want to ask one more question

Mr. Speaker: No, no Mr Supakar

Shri Sradhakar Supakar: The Draft Fourth Plan provided for an outlay of Rs 965 crores Now the hon Minister has said that it will be Rs 825 crores I find from the Demands for Grants in respect of the Ministry of Irrigation and Power that for this year and the last year, which are the first two years of the Plan, a total Plan outlay of only Rs 58,65,00,000 has been provided and that comes to less than one-tenth of the entire outlay May I know whether in the next three years the balance of about Rs. 750 crores will be spent?